

मनरेगा में लेबर बजट बढ़ाने के छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

17 मार्च, 2022 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम) के लेबर बजट में दो करोड़ 22 लाख मानव दविस की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बढि

- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंजूरी के बाद अब प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये मनरेगा के तहत रोज़गार सृजन का लक्ष्य साढ़े 13 करोड़ मानव दविस से बढ़कर 15 करोड़ 72 लाख मानव दविस हो जाएगा।
- छत्तीसगढ़ ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत निर्धारित साढ़े 13 करोड़ मानव दविस रोज़गार सृजन का लक्ष्य वगित फरवरी माह में ही हासल कर लिया था।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस वर्ष अब तक मनरेगा के अंतर्गत 28 लाख से अधिक परिवारों के करीब 54 लाख पाँच हज़ार श्रमकों को काम दिया गया है। इस दौरान चार लाख 75 हज़ार 374 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोज़गार भी मुहैया कराया गया है।